भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 270

सोमवार, 02 फरवरी, 2026/13 माघ, 1947 (शक)

श्रम शक्ति नीति 2025 के अंतर्गत डेटा संग्रह

270. श्री प्रद्युत बोरदोलोई:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का श्रम शक्ति नीति 2025 के मसौदे के तहत राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) प्लेटफॉर्म के माध्यम से श्रमिकों के शैक्षिक और कौशल संबंधी ब्यौरे को एकत्र करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो संग्रहण के तरीके, गोपनीयता संबंधी चिंताओं के समाधान और एकत्रित किए जाने वाले विवरण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उक्त आंकड़ों को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा शैक्षणिक संस्थानों की रोजगार क्षमता और कौशल प्रमाण-पत्रों के आधार प्रदत्त उन रैंकिंग से जोड़ने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त नीति के अंतर्गत कौशल प्रमाण-पत्रों के प्रमाणीकरण, सत्यापन के लिए और उनको मान्यता प्रदान करने के लिए प्रस्तावित कार्यढांचे का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने "श्रम शक्ति नीति 2025 - राष्ट्रीय श्रम और रोजगार नीति" के मसौदे को एक विस्तृत विज़न दस्तावेज के रूप में तैयार किया है जिसका उद्देश्य कामगारों, जिनमें महिलाएं, अनौपचारिक क्षेत्र के कामगार और स्व-रोजगार वाले कामगार शामिल हैं, के लिए एक समावेशी, निष्पक्ष और लचीला पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जिससे भारत वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने की ओर तेज़ी से अग्रसर होगा।

मसौदा नीति में राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) को रोजगार के लिए भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है, जो समावेशी रोजगार मिलान, प्रमाण पत्र सत्यापन और कौशल संरेखण के लिए तकनीकी रीढ़ के रूप में कार्य करता है।

मसौदा नीति में, विशेष रूप से उभरते क्षेत्रों में, कार्यबल के रोजगार क्षमता से जुड़े कौशल, पुनः कौशल और कौशल संवर्धन को बढ़ावा देकर कौशल उन्नयन और रोजगार के अवसरों में वृद्धि की परिकल्पना की गई है। मसौदा नीति में हरित नौकरियों को बढ़ावा देने, एआई-सक्षम प्रणाली, कम कार्बन उद्योगों में नवाचार और टिकाऊ क्षेत्रों में आजीविका के नए अवसरों के निर्माण सहित प्रौद्योगिकी आधारित विकास और हरित परिवर्तन मार्गों के माध्यम से रोजगार सृजन पर जोर दिया गया है।

*****